अध्याय 6

प्रभाव आकलन

अध्याय 6 प्रभाव आकलन

लेखापरीक्षा द्वारा चार नमूना-जाँचित जिलों में 24 निर्माण स्थलों **(परिशिष्ट 6.1)** का संयुक्त भौतिक सत्यापन[87] (जे. पी. वी.) किया गया (अक्टूबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच)। स्थल दौरों के दौरान निर्माण स्थलों पर उपस्थित कर्मकारों (220 कर्मकार) से उनकी पंजीकरण स्थिति और उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त की गई थीं। इसके अलावा, पंजीकृत कर्मकारों को लाभ प्रदान करने और उनकी शिकायतों (यदि कोई हो) के निवारण में बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच) 400 पंजीकृत कर्मकारों का एक लाभार्थी सर्वेक्षण किया, जिन्होंने 10 कल्याणकारी योजनाओं के तहत कोई लाभ प्राप्त किया था। सर्वेक्षण एक अनुकूलित प्रश्नावली के माध्यम से आयोजित किया गया था, जो बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं पर आधारित था।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन और लाभार्थी सर्वेक्षण से निम्नलिखित उद्घटित हुई:

6.1 मूलभूत सुविधाओं का अभाव

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 40 के अनुसार, राज्य सरकार सन्निर्माण कर्मकारों की उनके रोजगार के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में नियम बनाती है, साथ ही उन्हें उपकरणों, जिन्हें प्रदान करने की आवश्यकता है, उपलब्ध कराना है। झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड नियमावली को अधिसूचित (अगस्त 2007) किया था जिसमें कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण से संबंधित उपायों को शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- जिन 24 निर्माण स्थलों का दौरा किया गया, वहां काम करने वाले 220 कर्मकारों में से केवल 34 कर्मकारों (15 प्रतिशत) को बोर्ड के साथ पंजीकृत पाया गया। शेष कर्मकार अपंजीकृत पाए गए और उन्हें बोर्ड द्वारा संचालित किसी भी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार, 186 कर्मकारों को पंजीकरण की जानकारी नहीं थी और वे बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए लाभों से वंचित रहे।

- झारखण्ड नियमावली के नियम 47 और 55 के अनुसार, नियोक्ताओं से यह अपेक्षा की गई थी कि कर्मकार निर्माण कार्य करते समय सुरक्षा जूते, जलरोधक जूते/कोट, हेलमेट, जैकेट आदि जैसे उपयुक्त सुरक्षा सामग्री पहनें। तथापि, किसी भी

---

[87] लेखापरीक्षा दल के सदस्य, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के एक कर्मचारी और भवन निर्माण विभाग के एक कर्मचारी शामिल हैं।

स्थल पर कर्मकारों को उचित सुरक्षा सामग्री के साथ कार्य करते हुए नहीं पाया गया, जैसा कि **चित्र 9** से **12** में देखा जा सकता है।

चित्र 9	चित्र 10
दलादली, रांची में केंद्रीकृत रसोई का निर्माण स्थल (23 नवंबर 2022)।	
चित्र 11	चित्र 12
अमृतपार, चास, बोकारो के पीछे हेल्प प्लस अस्पताल का निर्माण स्थल (2 दिसंबर 2022)	जिला स्कूल, धनबाद का निर्माण स्थल (23 दिसंबर 2022)

- बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 33 में प्रावधानित है कि प्रत्येक स्थान पर, जहां भवन या अन्य निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर नियोक्ता पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय उपलब्ध करायेगा, जैसा कि निर्धारित है, और ये ऐसी सुविधाजनक स्थिति में हों, जो निर्माण कर्मकारों के लिए हमेशा सुलभ हो, जब वे ऐसे स्थान पर हों। तथापि, दौरा किए गए किसी भी निर्माण स्थल पर शौचालय और मूत्रालय नहीं पाए गए।

- बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 34, में प्रावधानित है कि नियोक्ता, और कार्य स्थल के भीतर या जितना नजदीक संभव हो सके, सभी निर्माण कर्मकारों को अस्थायी आवास नि: शुल्क प्रदान करेगा, जो उसके द्वारा ऐसी अवधि के लिए नियोजित किया गया है जैसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य प्रगति पर है। तथापि, दौरा किए गए 24 स्थलों में से केवल चार स्थलों पर निर्माण कर्मकारों के लिए अस्थायी आवास पाए गए।

इसके बजाय, कर्मकारों को निर्माणाधीन इमारतों में रहते हुए देखा गया, जैसा कि **चित्र 13** में दिखाया गया है।

चित्र 13

पूर्वी सिंहभूम के बिरसा नगर में पीएम आवास योजना के निर्माण स्थल पर निर्माणाधीन भवन में रहने वाले कर्मकार (23 नवंबर 2022)।

- झारखण्ड नियमावली के नियम 241 और 255 के अनुसार, एक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एक सूचना, जो मजदूरी का भुगतान किये जाने वाली अवधि को दर्शाता हो, ऐसी मजदूरी के संवितरण का स्थान और समय, उसके निर्माण स्थल के एक विशिष्ट स्थान पर अंग्रेजी, हिंदी में और ऐसे निर्माण स्थलों पर नियोजित अधिकांश निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया गया है। तथापि, दौरा किए गए किसी भी निर्माण स्थल पर ऐसा कोई सूचना नहीं पायी गयी।

- झारखण्ड नियमावली के नियम 234 (ए) में कहा गया है कि नियोक्ता अपने निर्माण स्थल पर निर्माण कर्मकारों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्राथमिक उपचार पेटी या अलमारी सुनिश्चित करेगा। तथापि, दौरा किए गए किसी भी स्थल पर प्राथमिक उपचार पेटी/अलमारी उपलब्ध नहीं पाए गए।

- बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत, प्रत्येक प्रतिष्ठान को उसके प्रारंभ होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के अंदर पंजीकृत किया जाना था। तथापि, दौरा किए गए 24 निर्माण स्थलों में से केवल 8 स्थलों को प्रतिष्ठानों के रूप में पंजीकृत किया गया था।

- झारखण्ड नियमावली के नियम 40 में कहा गया है कि पचास या अधिक सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान को सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में नीति का एक लिखित विवरण तैयार करना होगा, और मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के लिए इसे प्रस्तुत करना होगा। ऐसी नीति में भवन निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण तथा निर्माण कर्मकारों की संगठनात्मक व्यवस्था, प्रमुख नियोक्ता, संवेदक, ट्रांस्पोर्टर या अन्य एजेंसियो की

ज़िम्मेदारियां, सुरक्षा के जोखिम का आकलन के लिये तकनीको और तरीको के सम्बंध में प्रतिष्ठान के इरादे और प्रतिबद्धतायें, स्वास्थ्य और पर्यावरण और उसके उपचारात्मक उपाय तथा भवन निर्माण कर्मकारों, प्रशिक्षको, पर्यवेक्षको, या निर्माण कार्य में लगे अन्य व्यक्तियो के प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है।

पांच निर्माण स्थलों[88] में 50 से अधिक कर्मकार कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने बोर्ड को सन्निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किए थे।

- चार नियोक्ताओं[89] को ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत आवश्यक श्रम लाइसेंस निर्गत किए गए थे, लेकिन उन्हे बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया गया था।

- झारखण्ड नियमावली के नियम 107 में कहा गया है कि नियोक्ता किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि कंक्रीट कार्य के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार व्यक्ति कार्य का नियमित निरीक्षण करेगा और निरीक्षण के दौरान निरीक्षक को सभी अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

जेपीवी के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि दौरा किए गए किसी भी स्थल पर ऐसे किसी भी अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, बोर्ड के नामित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण भी नहीं किए जा रहे थे।

इस प्रकार, बोर्ड ने नियोक्ताओं के अनिवार्य पंजीकरण, पंजीकरण के लिए कार्यरत कर्मकारों के बीच जागरूकता, निर्माण स्थलों का निरीक्षण और निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया था। इसके अलावा, निर्माण कर्मकारों के लिए निर्माण स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं, जैसे अस्थायी आवास, शौचालय, मूत्रालय और प्राथमिक उपचार पेटी, निर्माण स्थलों पर उपलब्ध नहीं किए गए थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2023) कि बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश (नवंबर 2022) निर्गत किए हैं, जिसमें नियोक्ताओं के पंजीकरण, निर्माण स्थलों का निरीक्षण, सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और निर्माण स्थलों पर कर्मकारों के लिए आश्रय, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा पेटी जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है।

---

[88] (1) मेसर्स केxसी इंटरनेशनल लिमिटेड, चंxxक्याx, बोxरो (2) एनसीसी लिमिटेड, सुलxxनxर बोxरो (3) मैxन प्रोजेक्ट लिमिटेड, निxसा, धxबाx के लिए रेलवे इन्xxस्ट्रक्चx (4) 500-शैxx वाले एमxएम मेxxल कॉxx एवं अस्पxx, डीxना, जमxxशेxxर का निर्माण और (5) मनिxल टाx मेडिxxल कॉलx, बxडीह, जमxxशेxxर में अकादमिक भवन का निर्माण

[89] (1) ग्लोxल इन्xx, अxगोx, राँx (2) 320 आवाx इxई, बिxसा नxर, जमxxशेxxर का निर्माण (3) केxxयकृx रसोई, का प्रस्तावित निर्माण राँx और (4) 300-शैx वाले होx गाx बैxक, धुर्वा, रांx का निर्माण

6.2 चार सौ पंजीकृत कर्मकारों के लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष

चार सौ पंजीकृत कर्मकारों के लाभार्थी सर्वेक्षण में निम्नलिखित का पता चला:

- बीस कर्मकार **(परिशिष्ट 4.2)** गैर-बीओसीडब्ल्यू कार्य में लगे हुए पाए गए थे, हालांकि उन्हें निर्माण कर्मकारों के रूप में पंजीकृत किया गया था और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ, जिनकी राशि ₹ 2.48 लाख थी, उन्हें प्रदान की गई थी।

- सर्वेक्षण में शामिल 40 आश्रितों में से जिन्हें पंजीकृत कर्मकारों की मृत्यु के उपरांत मृत्यु पर सहायता राशि मिली थी, छः आश्रितों ने स्वीकार किया कि उनके भाई-बहन भी थे। तथापि, यह देखा गया था कि मृत्यु पर सहायता अन्य आश्रितों/भाई-बहनों की सहमति प्राप्त किए बिना केवल एक आश्रित को दी गई थी, हालांकि झारखण्ड सरकार की अधिसूचना[90] के अनुसार मृत्यु पर सहायता की राशि सभी आश्रितों को देय थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2023) कि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के सचिव ने राज्य के सभी मंजूरी देने वाले अधिकारियों को निर्देश निर्गत किए हैं कि प्रत्येक योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के संबंध में आवेदनों की गहन जाँच के बाद ही सभी प्रकार के लाभों के भुगतान की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, मंजूरी देने वाले अधिकारियों को अमान्य भुगतानों के मामलों की जाँच करने और उन पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

अनुशंसा 11: बोर्ड निर्माण स्थलों के निरीक्षण के लिए वार्षिक योजना बना सकता है, ताकि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की पहचान की जा सके और उस पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

[90] ज्ञापांक 02/(बीओसीडब्ल्यू अधिनियम)-11/2015 दिनांक 04.11.2015